अंतर को पाटने का सवाल : भारत और 'जेंडर गैप रिपोर्ट'

द हिंदू

पेपर-III (सामाजिक न्याय)

वार्षिक 'जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023' में भारत पिछले साल की तुलना में आठ पायदान ऊपर चढ़ गया है और अब वह लैंगिक समानता के मामले में 146 देशों में से 127वें स्थान पर है। लेकिन यह बेहतर आंकड़ा, कुल लैंगिक अंतराल का तकरीबन 64.3 फीसदी तक कम होना, शायद ही खुशी का कोई सबब है। भारत के सामने इस सूचकांक के चार प्रमुख बिन्दुओं – आर्थिक भागीदारी एवं अवसर; शिक्षा प्राप्ति; स्वास्थ्य और उत्तरजीविता; राजनैतिक सशक्तिकरण में से हर एक में सुधार करने की गुंजाइश है ताकि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश का आधा हिस्सा अर्थव्यवस्था, विकास और समाज के समग्र कल्याण में योगदान दे सके। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों की बदौलत भारत ने शिक्षा और स्थानीय शासन में 40 फीसदी से ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व के साथ राजनैतिक सशक्तिकरण के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन, जैसा कि यह रिपोर्ट बताती है, महज 15.1 फीसदी सांसद ही महिलाएं हैं, जो "2006 में इस रिपोर्ट के पहले संस्करण के बाद से भारत में सबसे ज्यादा है"। संसद को इस हकीकत के मद्देनजर लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक पर कार्रवाई करके इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक को 1996 में संसद में पेश किया गया था। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के मामले में चीजें कहां खड़ी हैं, इस बात को समझने के लिए जरा इस तथ्य पर गौर करें: 1963 में एक राज्य का दर्जा पाने वाला नागालैंड अपनी पहली दो महिला विधायकों को 2023 में ही चुन सका।

Gender gap

India jumped eight spots to rank 127 in the Global Gender Gap Index, 2023. A look at how select countries fared

Rank	Country	Score	Rank change
1	Iceland	0.912	-
2	Norway	0.879	+1
59	Bangladesh	0.722	+12
103	Bhutan	0.682	+23
107	China	0.678	-5
115	Sri Lanka	0.663	-5
116	Nepal	0.659	-20
127	India	0.643	+8
142	Pakistan	0.575	+3

पुरुषों और महिलाओं को एक जैसी आर्थिक भागीदारी और अवसर मुहैया कराने के मामले में, भारत 40 फीसदी से भी कम समानता के साथ सबसे निचले पायदान पर है। एक तरफ जहां वेतन और आय में समानता के मामले में स्थितियां बेहतर हुई हैं, वहीं वरिष्ठ पदों और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। चिंता का एक और सबब स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के मामले में भारत का प्रदर्शन है। हालांकि, जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार ने एक दशक से ज्यादा वक्त तक धीमी प्रगति के बाद इस मसले पर समानता ला दी है। यह जरूरी है कि लड़कियों को स्कूल और कॉलेज के जरिए शिक्षा हासिल करने का मौका मिले। उन्हें सवैतनिक कार्यों की भी जरूरत है।

महिलाएं घर पर इतना ज्यादा अवैतनिक काम करती हैं कि उनमें से कई महिलाओं के पास भुगतान वाले काम को चुनने के लिए वक्त या ऊर्जा ही नहीं बचती है। लड़कियों को नौकरी सुनिश्चित करने वाली शिक्षा प्रदान करने से पोषण सहित विकास के तमाम सूचकांकों में स्वचालित तरीके से सुधार होगा और खराब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार कम उम्र में विवाह का दुष्चक्र टूटेगा। जहां महामारी ने जीवन की भंगुरता को उजागर किया, वहीं यह महिलाओं के लिए कहीं ज्यादा मुश्किल वक्त रहा। उनकी श्रम भागीदारी दर में गिरावट आई, जिससे उनकी घरेलू आय में कमी हुई। अक्सर, अगर महिलाओं को नौकरी मिल भी जाती है, तो भी उनके रास्ते में पितृसत्तात्मक और सांस्कृतिक मानकों के जरिए रुकावट डाली जाती है। इसके अलावा, उन्हें अक्सर अपनी सुरक्षा की भी चिंता करनी पड़ती है। महामारी ने भले ही 2030 तक लैंगिक समानता का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में हो रही प्रगति को रोक दिया हो, लेकिन इसमें मौजूद अंतर को पाटने की दिशा में पूरी ईमानदारी के साथ काम जारी रहना चाहिए।

जेंडर गैप रिपोर्ट 2023

विश्व आर्थिक मंच ने वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है। यह रिपोर्ट का 17वां संस्करण है। इस रिपोर्ट के अनुसार, लिंग समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है अर्थात भारत को पिछले वर्ष से 8 स्थानों का सुधार हुआ है।

रिपोर्ट 2023 के निष्कर्ष:

- किसी भी देश ने अभी तक पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है।
- लगातार 14वें वर्ष आइसलैंड (91.2%) शीर्ष स्थान पर है। यह एकमात्र ऐसा देश बना हुआ है जिसने अपने लिंग अंतर को 90% से अधिक कम कर दिया है।
- पिछले संस्करण के बाद से भारत में 1.4 प्रतिशत अंक और 8 स्थान का सुधार हुआ है और कुल लिंग अंतर 64.3% कम हो गया है ।देश ने शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन में समानता हासिल कर ली है।
- भारत आर्थिक भागीदारी और अवसर में केवल 36.7% समानता तक पहुँच पाया था।राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में, भारत ने 25.3% समानता दर्ज की है, जिसमें 15.1% सांसदों का प्रतिनिधित्व महिलाएँ करती हैं।
- पाकिस्तान 142 पर, बांग्लादेश 59 पर, चीन 107 पर, नेपाल 116 पर, श्रीलंका 115 पर और भूटान 103 पर हैं।

रिपोर्ट के बारे में:

- यह लैंगिक समानता को मापने के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा पहली बार 2006 में प्रकाशित एक वार्षिक सूचकांक है।
- यह चार प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति पर देशों का मूल्यांकन करता है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तीकरण।
- यह देशों का आकलन करता है कि वे अपने संसाधनों और अवसरों को अपनी पुरुष और महिला आबादी के बीच कितनी अच्छी तरह से विभाजित कर रहे हैं, इन संसाधनों और अवसरों के समग्र स्तर की परवाह किए बिना।
- यह अधिक जागरूकता के साथ-साथ नीति निर्माताओं के बीच अधिक आदान-प्रदान के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत का प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर हुआ है।
2. भारत का प्रदर्शन अपने सब पड़ोसी देशों में सबसे खराब है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 न ही 2

Que. With reference to Gender Gap Report 2023, consider the following statements:

1. India's performance has improved as compared to last year.
2. India's performance is the worst among all its neighboring countries.

How many of the above statements are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : a

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : 'भारत आज भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति असमानता से ग्रस्त है।' हाल ही में प्रकाशित वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के आलोक में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- उत्तर की शुरुआत में लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के बारे में संक्षेप में चर्चा करें।
- उत्तर के अगले भाग में लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 की कथन के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करें।
- अंत में आगे की राह दिखाते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।